ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 355-358

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य एवं भारत

आरती यादव
सहायक आचार्य, सैन्य एंव स्त्रातजिक अध्ययन विभाग,
दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ0प्र0), भारत

Received- 23.07.2020, Revised- 25.07.2020, Accepted - 27.07.2020 E-mail: artigkpuniv@gmail.com

सारांश : ***शीतयुद्ध के बाद के घटनाक्रम में गत दो दशकों में दुनिया में वैश्विक संरचना और परिचालन गतिशीलता में विचित्र तरह का परिवर्तन आया है। इसे देखते हुए भारत को अब नई विश्व व्यवस्था के अनुरूप अपनी विदेश नीति में भी परिवर्तन लाने की जरूरत है। अपनी विदेशी नीतियों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए उसे बदलाव की नई पहल करनी होगी। साथ ही उसे राष्ट्र समुदाय में स्वीकार्यता बढ़ानी होगी, खासतौर से विश्व व्यवस्था में शक्तियों के बीच पदाक्रम के अनुसार अपनी पोजीशन भी हासिल करनी होगी।***

कुंजीभूत शब्द– घटनाक्रम, दशकों, वैश्विक संरचना, परिचालन, गतिशीलता, विचित्र, परिवर्तन, व्यवस्था ।

वैश्विक परिदृश्य में यदि भारत को उभरती शक्ति का तमगा बरकरार रखना है तो उसे कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देना ही होगा, मसलन, क्या भारत के पास वो शक्ति है जिससे वह वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सके, क्या भारत ऐसी राजनीतिक और आर्थिक क्षमताओं से लैस है जो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अन्य लोगों को एक शक्ति के रूप में पहचान करने पर मजबूर कर दे, क्या भारत अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश की सीमाओं से बाहर हस्तक्षेपकारी क्षमता रखता है, आदि। यदि ऐसा है तभी भारत उभरती शक्ति के सपने को साकार कर सकता है तथा अन्य शक्तियों के बराबर खड़े होकर राष्ट्र समुदाय में अपनी पोजिशन को पहचान दिला सकता है।

भारत के लिए अवसर– यदि भारत उभरती शक्ति का परिणाम पाना चाहता है तो इसे तीन तरह से खुद को व्यक्त करना पड़ेगा (1) कठोर शक्ति की अवस्था (2) मृदु शक्ति की स्थित और (3) भाव प्रदर्शन क्षमता। इन तीनों ही स्थितियों के एक गहन विश्लेषण से भारत के नए कद का आकलन कर सकते है।

"पश्चिम से पूर्व की ओर भूराजनीतिक बलों का स्थानांतरण 21वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की एक निर्धारक विशेषता है और इस कायापलट का मुख्य पड़ाव होगा एशिया।" एशिया की सर्वश्रेष्ठता ने न केवल दुनिया के अग्रणी देशों के लिए, बल्कि भारत के लिए भी चुनौतियां खड़ी कर दी है। "पश्चिम के एक बार फिर अंतरस्थ होने और चीन की बढ़ती ताकत से मौजूदा वैश्विक व्यवस्था के खतरे में पड़ने के साथ, एशिया पर आधिपत्य के लिए एक जद्दोजहद शुरू हो गई है। भारत इस भावी उथल–पुथल के बीच में है।" यह कूटनीतिक डिजाइन एशिया की बदलती हुई भूराजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं से ही उपजा है। जैसे ही क्षेत्रीय डाइनैमिक्स बदलते हैं, एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ अमेरिका उन्हें पुनः संतुलित करने के लिए मान जाएगा और भारत इस रणनीति में बहुत 'महत्वपूर्ण' होगा।

यह क्षेत्रों में अमेरिकी मौजूदगी और नेतृत्व को परिभाषित करने की रणनीति है जो "आने वाले दशकों में वैश्विक व्यवस्था को आकार देगी।" एशिया का उद्भव वर्तमान सदी की एक निर्धारक विशेषता होगी। इसलिए, अमेरिका महसूस करता है कि उसका भविष्य एशिया के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। भविष्य के विकास के केन्द्र के रूप में एशिया "ताकतवर भूराजनीतिक बलों के मनोभाव को उद्दीप्त कर रहा है जो इस क्षेत्र को पुनः आकार दे रहे है।" चीन की चढ़ाई, जापान का लचीलापन, "वैश्विक कोरिया" का उदय, पूर्व की ओर देखता भारत और "दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच बढ़ती इंटरकनेक्टिविटी" ये सब संभवतः सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय शक्ति के उदय को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका की सक्रिय वचनबद्धता की अपेक्षा रखते है। स्थायी सुरक्षा माहौल और आर्थिक उदारता इस रणनीति के केंद्र हैं। जिन "स्तंभों" पर इसे बनाया जाएगा वे हैं– "गठबंधनों को मजबूत बनाना, उभरती शक्तियों के साथ भागीदारी को बढ़ाना, चीन के साथ एक स्थिर, लाभकर और रचनात्मक संबंध बनाना, क्षेत्रीय संस्थानों को सशक्त बनाना और एक ऐसी क्षेत्रीय आर्थिक संरचना का निर्माण करना जो साझा समृद्धि को बनाए रख सकें।"

भारत की क्षमताओं को लेकर अमेरिका और चीन के विचार अलग–अलग है। चीन समझता है कि उसे नियंत्रित करने के लिए अमेरिकी कूटनीति ने भारत को अपनी ओर आकर्षित किया है। अमेरिकी उप–राष्ट्रपति जो बिडेन की भारत यात्रा ने इसकी आशंकाओं को और

अनुरूपी लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

बल दिया। इसके कारण इसने अमेरिकी नीति की अतिश्योक्ति की और "एक स्वतंत्र रणनीतिक सक्रियक" के रूप में भारत की क्षमताओं का कम आकलन किया। यह भारत के सामने आई आर्थिक चुनौतियों से उत्पन्न हुआ। अमेरिका में भी कई लोग चीन के प्रतिभार के रूप में भारत की संभाव्यता को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। लेकिन भारत चीन को नियंत्रित करने के लिए अमेरिकी व्यवस्था के प्रति आकर्षित नहीं हुआ है, बल्कि एशिया–पेसिफिक में अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के पास आर्थिक, समुद्री, भौगोलिक और सांस्कृतिक कारण है। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति सभी आसियान सदस्यों और चीन के साथ दोस्ताना संबंधों को बढ़ावा देने में सफल रही है। एशिया पेसिफिक में अमेरिका के कूटनीतिक डिजाइन में भारत को इसके हाथों की कठपुतली मानना गलत है, क्योंकि भारत अपने हितों को किसी भी शक्ति से स्वतंत्र समझता है। जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत संधि बाध्यता के अन्तर्गत पूर्ण निष्ठा से अमेरिका का मित्र नहीं है। हालांकि भारत की क्षमताओं को पूनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है क्योंकि इसके विकास ने 2011 के उत्तरार्द्ध में गति खो दी थी जो 2013 में निकृष्ट ढंग से कम हो गई थी।" बढ़ती हुई दीर्घावधिक अमेरिकी ब्याज दरों ने चिंताएं उत्पन्न कर दी हैं कि देश किस तरह अपने विशाल चालू खाते की कमी का भुगतान करेगा।" भारत से तुलना में, चीन का आर्थिक प्रदर्शन बेहतर है इसके अलावा, अमेरिकी राजकोषों में इसके 132 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है जो मई 2013 तक सर्वाधिक निवेश था। यह अमेरिका के विदेशी ऋण से 23 प्रतिशत अधिक था। भारत सरकार ने इन महत्वपूर्ण पड़ोसियों के साथ सामरिक साझेदारी समझौते की आवश्यकता को अच्छी तरह से समझा है, खासकर तब जब आपके पास अपने पड़ोस में चीन के रूप में एक संभावित चुनौती मौजूद हो। एक तरफ इन देशों का विश्वास जीतना जरूरी है तो दूसरी ओर भौगोलिक लाभ और आर्थिक प्रगति भी प्राप्त करना आवश्यक है। चीन पूरे क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गया है। किसी भी अन्य देश द्वारा किए गए किसी भी अनुचित प्रयास का वह भरपूर जवाब दे सकता है। चाहे वह रूस हो या अमेरिका अथवा अन्य कोई देश। भारत ने अपने पड़ोस के साथ जो समझौते किए हैं वे इन देशों के साथ पुराने ऐतिहासिक–सांस्कृतिक संबंध पर आधारित हैं और उनके बीच आपसी विश्वास भी है। जहां तक रणनीतिक साझेदारी की बात है तो यह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कारकों पर आधार है, जो देशों के बीच एक दीर्घकालिक संपर्क है और विभिन्न प्रकार के संबंधों में खुद ही प्रकट होता है। भारत ने अब तक 30 से अधिक देशों के साथ सामरिक साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। सच बात तो यह है कि भारत के उत्तरी पड़ोस में सामरिक चिंताओं और सुरक्षा चुनौतियों ने उसे इन मैत्रीपूर्ण, संसाधन–संपन्न और अति आवश्यक पड़ोसियों के साथ सामरिक भागीदारी समझौते (एसपीए) के लिए प्रेरित किया है। पिछले दस वर्षों में भारत ने मध्य एशियाई गणराज्यों, कजाकिस्तान (2009), उज्बेकिस्तान (मई 2011) और अफगानिस्तान (अक्टूबर 2011) और मंगोलिया (मई 2015) के साथ दो रणनीतिक साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, भारत ने सभी पांच मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ रक्षा सैन्य सहयोग पर भी हस्ताक्षर किए है।

जहां तक भारत के उत्तरी पड़ोस की ओर इसकी नीतियों का सवाल है, इसमें कई पहल करने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक बार में सभी मध्य एशियाई गणराज्यों का दौरा करने वाले पहले भारतीय नेता बन गए और पिछले छह दशकों में मंगोलिया जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे, क्योंकि दोनों देशों के बीच दिसंबर 1955 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। तब से कोई भी प्रधानमंत्री वहां के दौरे पर नहीं गया था। नवंबर 2014 में नेपेईडा (म्यांमार की राजधानी) में आसियान शिखर सम्मेलन में, भारत द्वारा भारत की लुक ईस्ट पालिसी की घोषणा करने के कुछ ही महीनों बाद ही पीएम मोदी ने न केवल उत्तर की ओर देखा, बल्कि सभी स्तरों पर इन भारत–मित्र पड़ोसियों के साथ दीर्घकालिक उपयोगी संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए तत्परता से काम किया। मई से दिसंबर 2015 के बीच, पीएम मोदी ने पड़ोस के इन देशों का दौरा किया यानी मंगोलिया (16–17 मई), मध्य एशियाई गणराज्य (6–13 जुलाई) और अफगानिस्तान (25 दिसम्बर)। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री पहले भारतीय नेता हों जो इन देशों में गए हों, लेकिन इससे पहले जो भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इन देशों में दौरे के लिए जाते थे वे एक समय में एक देश, एक मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित कर रहे थे, जबकि पीएम मोदी ने सभी देशों को समान प्राथमिकता दी। यहां तक कि किर्गिस्तान जो पिछले 25 वर्षों में भारतीय नीति निर्माताओं द्वारा पूरी तरह से उपेक्षित रहा, उसे मोदी की मध्य एशिया नीति में प्रमुखता मिली। किर्गिज राष्ट्रपति को 2019 में भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया।

मंगोलिया में पीएम मोदी ने सामरिक साझेदारी सहयोग समझौते सहित मंगोलिया के साथ 14 समझौतों

ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। अपने मध्य एशिया दौरे के दौरान, पीएम मोदी ने इन गणराज्यों के शीर्ष राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की, कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया और मध्य एशियाई नेताओं को संबोधित किया। साथ ही कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। जिनमें तुर्कमेनिस्तान (आँठ), कजाकिस्तान (पांच), किर्गिस्तान (चार), उज्बेकिस्तान (तीन) और ताजिकिस्तान (दो) शामिल है। इसमें भी कजाकिस्तान के साथ महत्वपूर्ण नागरिक परमाणु सहयोग समझौता और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ रक्षा समझौते शामिल हैं। इसके अलावा, भारत और मध्य एशियाई गणराज्य के बीच कई व्यापारिक समझौतों और आर्थिक सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

परंतु उपरोक्त परिस्थितियों के साथ–साथ आज सम्पूर्ण विश्व एक अदृश्य शत्रु कोविड–19, कोरोना महामारी से जूझ रहा है, आज पूरा विश्व लाकडाउन से गुजर रहा है।

कोविड–19 के संक्रमण का वर्तमान वैश्विक परिदृश्य एवं भारत– दुनिया इस समय कोविड–19 के संक्रमण को झेल रही है, जो नया कोरोना वायरस की बीमारी है। लगभग हर दिन इसके नये क्षेत्रों में फैलने की खबरें आ रही है। 2 मार्च, 2020 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनिया भर में 89000 मामलों की 65 से अधिक देशों में पुष्टि हो चुकी है और 27 देशों में इसके स्थानीय संक्रमण की खबर है। चीन के अलावा, यह दक्षिण कोरिया, ईरान, इटली और जापान में महामारी का रूप ले चुकी है और ये मामले केरल, राजस्थान, दिल्ली और तेलंगाना में प्रकाश में आए है। अमेरिका, इटली और जर्मनी जैसे धनी और संसाधन संपन्न देशों में इस बीमारी के स्थानीय संक्रमण की खबरें हैं। डॉ0 नैन्सी मेसोनियेर, अमेरिकी सीडीसी ने कहा है, 'अब यह प्रश्न नहीं है कि यह होगा की नहीं, बल्कि यह कि यह कब होगा और कितने लोग इस देश में इससे गंभीर रूप से संक्रमित होंगे।' और इसकी भयावहता को नीचे दिये गये ग्राफ से समझ सकते है– जो 11 मई 2020 का है।

कोरोना अटैक (भारत)

कुल मामले	नए मामले	24 घंटे में मौतें	कुल मौत
62,939	3,277	128	2,109

विश्व में

कुल मरीज 41,33,869	
ठीक हुए	मौतें
14,55,525	2,81,139

तमिलनाडु में कुल संक्रमितों की संख्या दिल्ली से ज्यादा

राज्य	कुल मामले	नए मामले	ठीक हुए	कुल मौत
महाराष्ट्र	20,228	1165	3,800	779
गुजरात	8,195	398	2,545	493
तमिलनाडु	7,204	669	1,959	47
दिल्ली / गौतमबुद्ध नगर	6923 / 218	381 / 02	2,069 / 136	73 / 02
राजस्थान	3,573	45	2,176	107
मध्य प्रदेश	3,614	157	1,480	211
उत्तर प्रदेश	3,462	89	1,504	74
आन्ध्र प्रदेश	1,980	50	925	45

अमेरिका में लगातार बढ़ रहा संक्रमितों का आंकड़ा

देश	कुल मामले	नए मामले	ठीक हुए	कुल मौत
अमेरिका	13,49,585	25,211	2,38,081	80,100
स्पेन	2,64,663	1,880	1,76,439	26,621
इटली	2,18,268	1,083	1,03,031	30,395
ब्रिटेन	2,15,260	3,896	N/A	31,587
रूस	2,09,688	11,012	34,306	1,915
फ्रांस	1,76,658	579	56,038	26,310
जर्मनी	1,71,324	681	1,44,400	7,549
ब्राजील	1,56,061	9,058	61,685	10,656

व्यवस्था को दुरूस्त करना– भारत में इसके तेजी से फैलने की उम्मीद करनी चाहिए क्योंकि यह तेजी से संक्रमित होने वाला है। भारत को इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा तॉकि इसका मुकाबला किया जा सके। अगर भारत में यह महामारी की शक्ल नहीं लेता है तो भी हमें नये तरह के संक्रमणों से बचने की तैयारी पूरी रखनी चाहिए। पिछले दशकों में हम भारत में स्वाइन लू और निपाह का संक्रमण झेल चुके हैं। इसके लिए होने वाली तैयारियों पर होने वाला खर्च निवेश है, जो हमें तत्काल या स्थिति के बिगड़ने पर फायदा पहुंचाएगा। कोविड–19 ने हमें मौका दिया है कि हम अपनी व्यवस्था को दुरूस्त करें। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि इसके फैलने के स्तर पर इससे निपटना। शुरूआती दिनों में जब यात्रा–संबंधि तमाम मामले कम और संभालने लायक होते हैं, जैसा कि अभी है, तो व्यापक स्क्रीनिंग, सभी संदिग्धों की जांच और संपर्कों का पता लगाने से इसके फैलाव को सीमित किया जा सकता है। पर एक बार जब संक्रमण मजबूती से समुदाय में जड़ जमा लेता है और स्थानीय बन जाता है, तो उस समय यह हमारी प्रयोगशालाओं पर शीघ्रता से दबाव डालना शुरू कर देता है। उस स्थिति में हमारी रणनीति इसको सीमित करने से इसको खत्म करने की हो जाती है तॉकि स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराए नहीं।

हमारी रणनीति– भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

बहुत कमजोर और बिखरी हुई है। इसके लिए सरकारी और निजी क्षेत्र के साथ–साथ पारंपरिक स्वास्थ्य व्यवस्था को भी साथ लेकर चलना होगा। इसके अलावा पुलिस, अग्निशमन सेवा, परिवहन, पर्यटन, खाद्य आपूर्ति और अन्य क्षेत्रों के साथ तालमेल बैठाना होगा। यह प्रत्युत्तर समानुपातिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए और सब कुछ पारदर्शी और मानव अधिकारों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। बड़ी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए गठित राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) का प्रयोग किया जाना चाहिए और उसे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ तालमेल बैठाने का काम सौंपा जाना चाहिए। उसे एक वेब पोर्टल शुरू करना चाहिए जो इसी कार्य के लिए हो और जिसमें महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए डैश बोर्ड की व्यवस्था हो जिसके माध्यम से वर्तमान मामले, दिशानिर्देशों, खतरों और सूक्ष्म स्तर की योजनाओं की जानकारी दी जाए। पारदर्शिता और तथ्यों पर आधारित सूचना संकट के समय काफी महत्वपूर्ण होती है। अफवाहों को रोकती है।

ईबोला का उदाहरण– किसी महामारी से मुकाबला करने के लिए सरकार, उसकी संस्थाओं और अपने ही नागरिक समुदायों में विश्वास बहुत जरूरी है। किसी महामारी को रोकने में विफलता का स्वास्थ्य पर तात्कालिक और दूरगामी प्रभाव होगा। 2014–2015 में पश्चिम अफ्रीका में ईबोला के संक्रमण ने वहां की कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी, मरीजों के साथ प्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले कई स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर इसके शिकार हुए। इसलिए महामारी से निपटने के कार्यक्रम का असर नियमित कार्यक्रमों पर नहीं पड़ना चाहिए। एनसीएमसी के लिए यह बहुत ही चुनौती भरा होगा। संकट से निपटने के लिए राज्य और जिलास्तरीय समितियों के साथ मिलकर निर्धारित करना चाहिए कि चीन में जिस कलस्टर कंटेनमेंट को आजमाया गया, भारत के संदर्भ में कारगार होगा कि नहीं और अगर हां, तो इसे कब शुरू किया जाए और कब समाप्त किया जाए।

खतरे के बारे में जानकारी– भारत में संक्रमण रोकने और उसको नियंत्रित करने की प्रैक्टिस खामियों से भरा है। इसमें बचाव के उचित संसाधनों के अभाव से लेकर सुरक्षा को लेकर लापरवाही भी शामिल है। इसके खतरे के बारे में जानकारी को इस तरह से प्रचारित करना चाहिए कि लोगों को अस्पताल तक पहुंचने में किसी तरह की असुविधा नहीं हो।

संसाधनों को जुटाना और इस कार्य में लगाए जाने वाले लोगों को प्रशिक्षित करना बहुत जरूरी है और गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। कंपनियों को निर्णय करना चाहिए कि वे लोगों को घर से काम करने की छूट दे सकती हैं कि नहीं। जिन्हें संक्रमण होने के कारण अलग रखा गया है, उनकी छुट्टी के बारे में नीतियों को दुरूस्त करने आदि के बारे में उन्हें उचित निर्णय लेना चाहिए। चीन ने जो कदम उठाए हैं, उनकी वजह से दुनिया भर के देशों को काफी समय मिल गया और इसलिए हमें इस समय को हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए। बुरे समय के लिए तैयार रहना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. प्रोफसेर आर0एस0 यादव, एक उभरती शक्ति के रूप में भारत : अवसर और चुनौतियां, वर्ल्ड फोकस अप्रैल, 2014, पृ0 3.
2. प्रोफसेर आर0एस0 यादव, एक उभरती शक्ति के रूप में भारत : अवसर और चुनौतियां, वर्ल्ड फोकस, अप्रैल, 2014, पृ0 4.
3. Deepak Lal, The dove and the wolf, Business Standard, 21/9/2013, p. 11.
4. T.E. Donilon, speech as prepared for deliv ery, The United States and Asia Pacific in 2013, The Asia Sociey, 11 March, 2013.
5. T.E. Donilon, speech as prepared for deliv ery, The United States and Asia Pacific in 2013, The Asia Sociey, 11 March, 2013.
6. Arvind Gupta, America's Asia Strategy in Obama's second Term, IDSA Comment, March 21, 2013.
7. Andy Mukharjee, India's Growth Marathon, Business Standard, 17 September, 2013, p. 9.
8. China has a business motive in buying so much US debt, that is make the Yuan cheaper thereby making its exports cheaper for for eign buyers. Thomas Kenny, about.com.
9. डॉ0 महेश रंजन देबता, अपने उत्तरी पड़ोसियों के प्रति भारत की नीति, वर्ल्ड फोकस अक्टूबर, 2019, पृ0 8.
10. डॉ0 महेश रंजन देबता, अपने उत्तरी पड़ोसियों के प्रति भारत की नीति, वर्ल्ड फोकस अक्टूबर, 2019, पृ0 11.
11. राष्ट्रीय सहारा, 7 मार्च, 2020, पृ0 2.

*****